भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 639

07 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

घरेलू इस्पात उत्पादन क्षमता को दुगना किया जाना

639. श्री इरण्ण कडाडि:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2030-31 तक घरेलू इस्पात उत्पादन क्षमता को दोगुने से भी ज्यादा बढ़ाकर 300 मेट्रिक टन करने के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है, यदि हां तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरे क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु कार्यबल गठित किया है और, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त कार्यबल घरेलू इस्पात उद्योग पर आयातित इस्पात का प्रभाव और चालू परियोजनाओं में आयातित इस्पात के उपयोग के प्रतिशत के स्तर का भी विश्लेषण करेगा?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) से (ग): देश की मौजूदा वार्षिक क्रूड इस्पात क्षमता 144 एमटी है और वर्ष 2030-31 तक इसके 300 एमटी तक पहुँचने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 का उद्देश्य इस्पात उत्पादकों को नीतिगत सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराना है। इस क्षेत्र की प्राथमिकता इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारत में विनिर्माण क्षेत्र में इस्पात क्षेत्र की कंपनियों द्वारा 40% निवेश वर्ष 2020-21* के दौरान किया गया है। इसके अतिरिक्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के उपरांत, स्वदेशी रूप से विनिर्मित इस्पात का प्रयोग बढ़ाने एवं आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस्पात मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहलें की गई हैं।

{* स्रोत: इकोनोमिक ऑउटलुक, सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) प्रा. लि.}

(i) मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।

(ii) घरेलू विनिर्मित स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

(iii) 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।

संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) तथा इस्पात विकास एवं वृद्धि संस्थान (आईएनएसडीएजी) ने इस्पात मंत्रालय के साथ विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है। इस उद्देश्य से की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) इस्पात मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था के विकास - भवन एवं निर्माण क्षेत्र के लिए इस्पात उपयोग को बढ़ाने हेतु समर्थकारी प्रक्रियाओं पर अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई), जापान के सहयोग से जापानी विशेषज्ञों को शामिल करके फरवरी, 2020 में नई दिल्ली, मुंबई और भुवनेश्वर में कार्यशालाओं और जनवरी, 2022 में वेबिनार का आयोजन किया है।

(ii) रेलवे और रक्षा क्षेत्र में घरेलू स्तर पर निर्मित इस्पात को बढ़ावा देने के लिए फरवरी, 2020 में रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(iii) तेल और गैस क्षेत्र में घरेलू स्तर पर निर्मित इस्पात को बढ़ावा देने के लिए जून, 2020 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से एक वेबिनार का आयोजन किया गया।

(iv) आवास एवं निर्माण क्षेत्र तथा नागर विमानन क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए अगस्त, 2020 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा नागर विमानन मंत्रालय के सहयोग से एक वेबिनार का आयोजन किया गया।

(v) ग्रामीण भारत में स्वदेशी इस्पात उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन विभाग एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा उद्योग मंत्रालय के सहयोग से अक्टूबर, 2020 में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(vi) इसके अतिरिक्त, आवास और निर्माण क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, बीआईएस, सीपीडब्ल्यूडी, तकनीकी संस्थानों (आईआईटी) और उद्योग जगत के सदस्यों के साथ एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का भी गठन किया गया है। जेडब्ल्यूजी ने 03 बैठकें आयोजित कीं और जेडब्ल्यूजी के अंतर्गत केन्द्रीय समिति ने अभी तक 10 से अधिक बैठकें आयोजित की हैं।

(vii) इस्पात मंत्रालय ने लॉन्ग स्पेन (30मी., 35 मी. तथा 40 मी.) इस्पात आधारित पुलों की डिजाइन को विकासित करने के लिए आईएनएसडीएजी, आईआईटी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के विशेषज्ञों तथा उद्योग के विशेषज्ञों को शामिल करके एक समिति का भी गठन किया है। **30 मीटर के लिए डिजाइन को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है और दिनांक 04.01.2022 को प्रस्तुत कर दिया गया है।**

(viii) सितंबर, 2020 में तेल एवं गैस क्षेत्र में स्वदेशी इस्पात को बढ़ावा देने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने के उद्देश्य से पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से एक समिति का गठन किया गया है। **इस समिति ने अगस्त, 2021 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।**

****